भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 475

जिसका उत्तर 6 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना

475. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री रवि किशन:
श्री भोलानाथ 'बी.पी.सरोज':
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री जी. सेल्वम:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डीबीयू को शुरू करने के लक्ष्य और उद्देश्य का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस तरह से डीबीयू पारंपरिक बैंक शाखा से अलग होगा;

(ग) डीबीयूएस की स्थापना के लिए जिलों की सूची को अंतिम रूप देते समय किन कारकों को ध्यान में रखा गया है;

(घ) बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने बैंकिंग में शत-प्रतिशत डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं;

(च) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अधिकांश ग्रामीण ग्राहक डिजिटल बैंकिंग से अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा डीबीयूएस का पूरे देश में विस्तार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत कराड)

(क): 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) को 16 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, देश भर में 84 डीबीयू परिचालनरत हैं। डीबीयू को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में तेजी लाने और व्यापक बनाने के साथ-साथ डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डीबीयू का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ख): डीबीयू डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए निर्धारित डिजिटल बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित विशेष निर्धारित स्थान व्यवसायिक इकाइयां/केंद्र हैं। डीबीयू स्व-संचालित और सहायता पद्धति, दोनों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे ग्राहकों को एक दक्ष, पेपरलेस, सुरक्षित और कनेक्टेड वातावरण में 24*7 सुविधाजनक पहुंच और उन्नत डिजिटल अनुभव प्राप्त होता है।

(ग): आरबीआई और आईबीए द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पहले 75 डीबीयू के चयन के लिए व्यापक मापदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) टियर-2 से टियर 6 केंद्र (अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर);

(ii) प्रायोगिक कार्यक्रम "डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम का विस्तार और प्रसार" के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अभिचिन्हित जिले; और

(iii) महिलाओं और युवाओं की अधिक प्रतिशत आबादी वाले जिले, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भौगोलिक और कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, एसएचजी का विस्तार और मध्यम स्तर तक डिजिटल माध्यमों को अपनाना इत्यादि।

(घ) और (ड.): बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से उन्नत और निर्विघ्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपना रहे हैं। इसके अलावा, देश के लोगों के लिए निर्विघ्न और निर्बाध बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई और बैंकों द्वारा कई पहलें की गई हैं। कुछेक पहल भीम-यूपीआई, यूपीआई-123, आधार पेमेंट ब्रिज, एईपीएस इत्यादि हैं।

ऐसे पहल के परिणामस्वरूप, भारत में डिजिटल लेन-देन में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, जो पिछले चार वित्तीय वर्षों में डिजिटल लेन-देन की मात्रा में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	**मात्रा (लाख में)**
2018-19	2,32,602
2019-20	3,40,025
2020-21	4,37,445
2021-22	7,197,68

श्रोत: आरबीआई

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से पिछले चार वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान की मात्रा में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 21-22 में दर्ज यूपीआई लेनदेन 45 बिलियन था, जो पिछले 3 वर्षों में 8 गुना वृद्धि और पिछले 4 वर्षों में 50 गुना वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान एईपीएस लेनदेन में पिछले 3 वर्षों में 4 गुना और पिछले 4 वर्षों से 10 गुना की वृद्धि हुई है।

(च) और (छ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण किया गया है, जो 3 मापदंडों अर्थात वित्तीय ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार पर आधारित है। 21 के कुल स्कोर पर आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए औसत शहरी और ग्रामीण स्कोर नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	**शहरी**	**ग्रामीण**
उत्तर	11.5	11.5
पूर्व	12.1	12.1
केंद्रीय	12.5	12.1
पश्चिम	12.6	12.5
दक्षिण	11.2	10.3

इसके अलावा, सरकार, आरबीआई और बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे:

(i) ग्रामीण नागरिकों के लिए उपलब्ध डिजिटल वित्त विकल्प के संबंध में जागरुकता सत्र के संचालन के लिए ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त – जागरुकता सृजन और पहुंच (डीएफआईएए) योजना;

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है;

(iii) आरबीआई डिजिटल भुगतान के संबंध में जागरुकता लाने के लिए अपने आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है;

(iv) आरबीआई डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग करते समय, कैसे सतर्क रहे, के संबंध में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए मल्टी चैनल जन-जागरण (पब्लिक अवेयरनैस) मीडिया कैंपेन का संचालन कर रहा है। साथ ही आरबीआई ने "डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने", डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर मल्टी लिंगुअल मीडिया कैंपेन भी संचालित किया है;

(v) आरबीआई वित्तीय शिक्षा के प्रचार के लिए वर्ष 2016 से प्रति वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है;

(vi) बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और *99# (यूएसएसडी) के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" के संबंध में अपने एफएलसी के माध्यम से विशेष कैम्पों का आयोजन करता है;

(vii) बैंकों की ग्रामीण शाखाएं वित्तीय जागरुकता संदेश (फाइनेंशियल अवेयरनैस मैसेज) बुकलेट और यूपीआई और *99# यूएसएसडी जैसे दो डिजिटल प्लेटफार्म के सभी संदेशों को कवर करने के लिए कैम्पों का आयोजन करता है; और

(viii) बैंक मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराते समय जागरुकता का भी सृजन करते हैं क्योंकि स्थानीय निवासी के साथ उनकी जान-पहचान होती है।

(ज): 'डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर), भुगतान बैंकों (पीबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) को जब तक कि अन्यथा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो, प्रत्येक मामले में आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति दी गई है।

*****

अनुबंध

"डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 6.2.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 475 का भाग (क)

डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) की सूची			
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**डीबीयू/जिले का नाम**	**बैंक आवंटित डीबीयू**
1	अंडमान एंड निकोबार (यूटी)	पोर्ट ब्लेयर	भारतीय स्टेट बैंक
2	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
3	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
4	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	यस बैंक
5	असम	बोंगईगांव	पंजाब नैशनल बैंक
6	असम	बक्सा	भारतीय स्टेट बैंक
7	बिहार	पटना (दानापुर)	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
8	बिहार	मुजफ्फरपुर	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
9	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़ (ग्रामीण)	एचडीएफसी बैंक
10	छत्तीसगढ़	बालोद	भारतीय स्टेट बैंक
11	छत्तीसगढ़	महासम्मन्द	भारतीय स्टेट बैंक
12	दादरा नगर हवेली	सिल्वासा	बैंक ऑफ बड़ौदा
13	दमन एंड दीव (यूटी)	नॉर्थ गोवा	पंजाब नैशनल बैंक
14	गोवा	साउथ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
15	गोवा	वड़ोदरा	बैंक ऑफ बड़ौदा
16	गुजरात	सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
17	गुजरात	मेहसाणा	कोटक महिंद्रा बैंक
18	गुजरात	सूरत	कोटक महिंद्रा बैंक
19	हरियाणा	फरीदाबाद	एचडीएफसी बैंक
20	हिमाचल प्रदेश	सोलन	इंडियन ओवरसीज बैंक
21	जम्मू एंड कश्मीर (यूटी)	जम्मू	जम्मू एंड कश्मीर बैंक
22	जम्मू एंड कश्मीर (यूटी)	श्रीनगर	जम्मू एंड कश्मीर बैंक
23	झारखंड	ईस्ट सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
24	झारखंड	जमशेदपुर	डीबीएस बैंक
25	झारखंड	रांची	जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
26	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	केनरा बैंक
27	कर्नाटक	रायचुर	केनरा बैंक
28	कर्नाटक	मंगलुरु	कर्नाटक बैंक
29	कर्नाटक	मैसूर	कर्नाटक बैंक
30	केरल	एर्नाकुलम	केनरा बैंक
31	केरल	त्रिशूर	साउथ इंडियन बैंक
32	केरल	पलक्कड़	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
33	लद्दाख (यूटी)	लेह	बैंक ऑफ बड़ौदा
34	लक्षद्वीप (यूटी)	कवारती	केनरा बैंक
35	मध्य प्रदेश	इटारसी (होशंगाबाद)	ऐक्सिस बैंक
36	मध्य प्रदेश	इंदौर	बैंक ऑफ बड़ौदा
37	मध्य प्रदेश	सागर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
38	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
39	महाराष्ट्र	सतारा	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
40	महाराष्ट्र	नागपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

41	मणिपुर	काकचिंग	भारतीय स्टेट बैंक
42	मेघालय	री भोई (आकांक्षी)	भारतीय स्टेट बैंक
43	मिजोरम	आइजोल	पंजाब नैशनल बैंक
44	नागालैंड	कोहिमा	आईसीआईसीआई बैंक
45	नागालैंड	दीमापुर	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
46	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यूटी)	साउथ दिल्ली	इंडियन बैंक
47	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यूटी)	वैस्ट दिल्ली	पंजाब नैशनल बैंक
48	ओडिशा	खुर्दा	बैंक ऑफ इंडिया
49	ओडिशा	क्योंझर	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
50	ओडिशा	पुरी	यूको बैंक
51	ओडिशा	कटक	यूको बैंक
52	पुदुचेरी (यूटी)	पुदुचेरी	आईसीआईसीआई बैंक
53	पुदुचेरी (यूटी)	कराईकल	इंडियन बैंक
54	पंजाब	जालंधर	इंडसइंड बैंक
55	पंजाब	फरीदकोट	पंजाब एंड सिंध बैंक
56	पंजाब	लुधियाना	पंजाब एंड सिंध बैंक
57	पंजाब	पटियाला	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
58	राजस्थान	बूंदी	ऐक्सिस बैंक
59	राजस्थान	विजयनगर, भीलवाड़ा	ऐक्सिस बैंक
60	राजस्थान	कोटा	बैंक ऑफ बड़ौदा
61	राजस्थान	करौली	बैंक ऑफ बड़ौदा
62	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
63	सिक्किम	नॉर्थ सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
64	सिक्किम	वैस्ट सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
65	तमिलनाडु	विरुद्धनगर	केनरा बैंक
66	तमिलनाडु	कोयंबटूर	केनरा बैंक
67	तमिलनाडु	करूर	आईसीआईसीआई बैंक
68	तमिलनाडु	तंजावुर	इंडियन ओवरसीज बैंक
69	तमिलनाडु	चेंगलपट्टू	इंडसइंड बैंक
70	तेलंगाना	खम्माम	सिटी यूनियन बैंक
71	तेलंगाना	जनगांव	भारतीय स्टेट बैंक
72	तेलंगाना	राजन्ना	भारतीय स्टेट बैंक
73	त्रिपुरा	गोमती	पंजाब नैशनल बैंक
74	त्रिपुरा	वैस्ट त्रिपुरा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
75	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	बैंक ऑफ बड़ौदा
76	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात ग्रामीण	बैंक ऑफ बड़ौदा
77	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	इंडियन बैंक
78	उत्तर प्रदेश	झांसी	पंजाब नैशनल बैंक
79	उत्तराखंड	हरिद्वार	एचडीएफसी बैंक
80	उत्तराखंड	देहरादून	आईसीआईसीआई बैंक
81	उत्तराखंड	नैनीताल	पंजाब नैशनल बैंक
82	पश्चिम बंगाल	नॉर्थ 24 परगना	फेडरल बैंक
83	पश्चिम बंगाल	साउथ 24 परगना	एचडीएफसी बैंक
84	पश्चिम बंगाल	नाडिया	पंजाब नैशनल बैंक

******